

प्रश्न सं. [ क. 3671 ]

(पारिशिष्ट -1)

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण**  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA**  
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)  
क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. (पूर्व) \ REGIONAL OFFICE M.P. (East)  
म.नं.-109, आदर्श नगर, नर्मदा रोड, जबलपुर (म.प्र.) 482 008  
H. No. - 109, Aadarsh Nagar, Narmada Road, Jabalpur (M.P.) 482 008  
दूरभाष / Phone : 0761 - 3585028, ईमेल / E-mail : rojabalpur@nhai.org, rojabalpuoffice@gmail.com




**भारतमाला**  
प्रगति के पथ पर प्रवृत्त  
**BHARATMALA**  
ROAD TO PROSPERITY

भा.रा.रा.प्रा./क्षे.का.-म.प्र./जबलपुर/विधान सभा/2024/3687

दिनांक 05/07/2024

प्रति,

मुख्य अभियंता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,  
निर्माण भवन, प्लाट नं. 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल  
दूरभाष नं. 0755-2551570,  
ई-मेल cepwdnhzonempbhopal@gmail.com

विषय: विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3671 द्वारा ) श्रीमती रीती पाठक, "सड़कों की मांग" के संबन्ध में।  
महोदय,

अतारांकित प्रश्न का इस कार्यालय के अंतर्गत विन्दुवार प्रतिउत्तर निम्नानुसार है:-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
(क)	क्या सीधी जिला मुख्यालय के समीप जमोडी कला से जोगीपुर तक उतरी बाईपास स्वीकृत करने की कोई योजना है। यदि हां तो कब तक स्वीकृत की जावेगी व इसकी लागत क्या है।	यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
(ख)	क्या उत्तरप्रदेश से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क प्रयागराज से कटरा-मऊगंज-पटपरा-सीधी-टिकरी हरचोक होते हुए मनेंद्रगढ़ (छ.ग.) तक हाईवे स्वीकृत करने की सरकार की कोई योजना है। इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं।	
(ग)	प्रदेश के हाईवे स्टेट हाईवे में जो भी टोल रोड है वहां अक्सर देखा जाता है की बड़ी संख्या में मवेशी सड़क में बैठे रहते हैं जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं इन मवेशियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार की क्या योजना है। क्या टोल मार्गों में दुर्घटना से मृत मवेशी कई दिनों तक सड़कों में पड़े रहते हैं इनको हटाने की कोई व्यवस्था है। यदि हां तो इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हाईवे पर सुचारु यात्रा सुनिश्चित करने, आवारा मवेशियों को हाईवे से हटाने एवं घटना प्रबंधन के लिए घटना प्रबंधन टीम की तैनाती की गयी है जो 24X7 आधार पर राजमार्गों पर गश्त करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवारा मवेशियों को हटाया जा रहा है जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम हो सके। इस समस्या के क्रियान्वयन के लिए भार.रा.प्रा. एवं राज्य सरकार को संयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है जिसमें की राज्य सरकारों के पास पूर्व से उपलब्ध CowCatcher वाहनों को NHAI के टोल प्लाजाओं पर पदस्थ कर एवं भार.रा.प्रा. की भी पूर्व से उपलब्ध पेट्रोलिंग टीम के साथ समन्वय स्थापित कर निराश्रित गौवशों को निकटतम गौशाला तक पहुँचाया जा सकता है।
(घ)	इस वित्तीय वर्ष में प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अलावा सीधी विधानसभा अंतर्गत कौन-कौन सी सड़क स्वीकृत की जानी है, विभाग से प्राप्त प्रस्ताव व जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई सड़क निर्माण संबंधी मांगों में कौन सी सड़क स्वीकृत की जा रही है।	यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

विशेष कार्यवाही अधिकारी (रामप्रियास पटेल)  
लोक निर्माण विभाग, प्रबंधक (तक.)  
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

मुख्य बजट वर्ष 2021-22 में सम्मिलित कार्यों के डी.पी.आर. की जानकारी के सम्बंध में।  
दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में

स.क्र.	जनप्रतिनिधि का नाम/पदनाम	विषय	जनप्रतिनिधि का संदर्भ	शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय का संदर्भ	लम्बाई (कि.मी. में)	संभावित लागत (लाख में)	की गई कार्यवाही	टीप
1	श्री केदारनाथ शुक्ल माननीय विधायक विधानसभा-सीधी	बाईपास मार्ग जमोड़ी कला (उत्तरी तरफ रेल्वे स्टेशन) जोगीपुर बाईपास मार्ग।	पत्र क्रमांक 225 दिनांक 24.01.2021	माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र क्रमांक / 4843/CMS/ MLA/077/21 भोपाल दिनांक 02.03.2021	13.92	8287.06	मुख्य अभियंता रीवा पत्र क्रमांक 862 दि.23.05.2022 से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्राक्कलन प्राप्त। जो दिनांक 29.05.2023 को आयोजित वित्तीय व्यय समिति की 101 वी बैठक में बजट प्रावधान से अधिक लागत वृद्धि होने के कारण अस्वीकृत है। (प्रकरण सी.एम. नॉनित-B में शामिल है)	9 (1) वर्ष 2021-22 के मुख्य बजट में मद क्रमांक 05 पर सरल क्रमांक 87 में लंबाई 10.00 कि.मी. एवं लागत राशि ₹. 850.00 लाख का शामिल है। (2) प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है।

मुख्य अभियंता यो/ब  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

विशेष करार/अधिकार  
लोक निर्माण विभाग,  
मध्य प्रदेश मंत्रालय, भोपाल